242

30 AUG 2019

दृष्टि The Vision

drishti

GENERAL STUDIES (Module – 8)

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

DTVF/19 (N-M)–M–**GS18**

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

Name: Alok Prasad

Mobile Number:

Medium (English/Hindi): Hindi

Reg. Number: *7100

Center & Date: MKN 30 Aug

UPSC Roll No. *(If allotted)*: 5907766

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।
प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:
There are TWENTY questions printed both in HINDI and ENGLISH.
All the questions are compulsory.
The number of marks carried by a question is indicated against it.
Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.
Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.
Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा भरा जाए *(To be filled by Evaluator only)*

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Reviewer (Signature)

खंड - क/ SECTION - A

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

1. सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 की प्रमुख विशेषताएँ कौन-सी हैं? यह विधेयक देश की पारदर्शी शासन व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है? (150 शब्द) 10

What are the key features of the Right to Information (Amendment) Bill 2019? How does the Bill affect the transparency regime in the country? (150 words) 10

भारत संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सुप्रीमकोर्ट ने सूचना के अधिकार अधिनियम को आवश्यक माना था। (इंडियन एक्सप्रेस केस)

सूचना के अधिकार अधिनियम का सूत्रपात मजदूर किसान ~~शक्ति~~ शक्ति संगठन (MKSS) की प्रभावी माँग के स्वरूप हुआ

प्रमुख विशेषताएँ - Bill

① हाल के अधिनियम में संशोधन द्वारा सरकार ने सूचना आयुक्त से संबंधित नियुक्ति, वेतन भत्ते, हटाने संबंधी प्रावधान को केंद्र सरकार के अधीन करना चाहा है।

② सरकार का दावा है कि चूँकि मुख्य सूचना आयुक्त का पद वैधानिक है अतः मुख्य निर्वाचन आयुक्त (जोकि संवैधानिक) के बराबर अधिकार नहीं दिए जा सकते

Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

इसका पारदर्शी शासन व्यवस्था पर प्रभाव

1. सूचना आयुक्त की नियुक्ति का राजनीतिकरण होगा।
   - → फलतः निष्पक्षता प्रभावित होगी
   - → पारदर्शी फैसलों के बजाय सरकार पक्षीय फैसले होंगे।

2. सुशासन की अवधारणा पर चोट

RTI
↓
पारदर्शिता
↓ ↓
जनता अधिकार सम्पन्न | सरकार जवाबदेह
↓
सुशासन

3. पारदर्शिता की अवधारणा प्रभावित होगी
ज्ञातव्य है कि RTI एक्ट के क्रियान्वयन में पहले से ही खामियाँ (देरी, PIO की नियुक्ति नहीं) विद्यमान है।

2nd ARC द्वारा RTI को पारदर्शिता की कुंजी कहा है। अतः RTI में किसी भी प्रकार का नकारात्मक परिवर्तन पारदर्शिता और सुशासन विरुद्ध होगा

Copyright – Drishti The Vision Foundation

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिये। सामान्यतः संशोधन प्रक्रिया की आलोचना क्यों की जाती है? (150 शब्द) 10

Describe the procedure of amendment of the Constitution of India under Article 368. Why this amendment procedure has been often criticized? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है।

A- 368

- सामान्य मामले
  - जिनमें सिर्फ विशेष बहुमत की आवश्यकता
  - उदाहरण
    - कार्यपालिका संबंधी प्रावधान इत्यादि
- विशिष्ट मामले
  - विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों से समर्थन
  - Ex! राष्ट्रपति या न्यायपालिका संबंधी प्रावधान etc

आलोचना का आधार

① जटिल वर्गीकरण → कुछ मामले सिर्फ विशेष बहुमत तथा कुछ में राज्यों के समर्थन

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

की जरूरत

2 कठोर प्रक्रिया

↳ राज्यसभा और लोकसभा दोनों में विशेष बहुमत कठोर प्रक्रिया है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

3. 'जनहित का प्रत्येक विषय जनहित याचिका का विषय नहीं हो सकता है'। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द) 10

'Every matter of public interest cannot be a matter of public interest litigation'. Comment. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

जनहित याचिका की शुरुआत P.N भगवती के न्यायिक नवाचारों के क्रम में हुई। जिसने न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा दिया।

हाल ही बढ़ती अत्यधिक PIL की संख्या ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है।

क्या जनहित का प्रत्येक विषय PIL का विषय हो सकता है।

पक्ष	विपक्ष
① जनहित का तात्पर्य ही है कि मामले में हस्तक्षेप करना जरूरी है ताकि वंचित वर्गों की आवाज सुनी जा सके	① जनहित से जुड़ा प्रत्येक मुद्दे का निवारण का कार्य न्यायपालिका के बजाय कार्यपालिका और विधायिका का है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

पक्ष	विपक्ष
(2) कभी कभी सरकार वोट बैंक या राजनीतिक बाध्यताओं के चलते सुधार नहीं कर पाती है। अतः PIL आवश्यक	(2) प्रत्येक मामले में हस्तक्षेप न्यायिक अतिक्रमण की सूची में आएगा
(3) ट्रांसजेंडर, समलैंगिक जैसे संवेदनशील और मानवता युक्त मुद्दों पर न्यायपालिका को निर्णय देना आवश्यक होता है क्योंकि इनकी आवाज नहीं सुनी जाती	(3) शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को ठेस पहुंचेगी।
	(4) सरकार बहुमत की आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। अतः उसे संतुष्ट करने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए

सारांशतः PIL पर अत्यधिक निर्भरता जहाँ एक तरफ न्यायिक अतिक्रमण को बढ़ा सकते है। तो वहीं वंचित वर्गों हेतु इनकी आवश्यकता है। अतः यहाँ एक संतुलन की आवश्यकता है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

4. भारत में कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण कई सीमाओं से ग्रस्त है। विवेचना कीजिये।

(150 शब्द) 10

Parliamentary control over executive in India is riddled with several limitations. Discuss.

(150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। जिसमें कार्यपालिका ~~कि~~ विधायिका के माध्यम से नियंत्रित होती है।

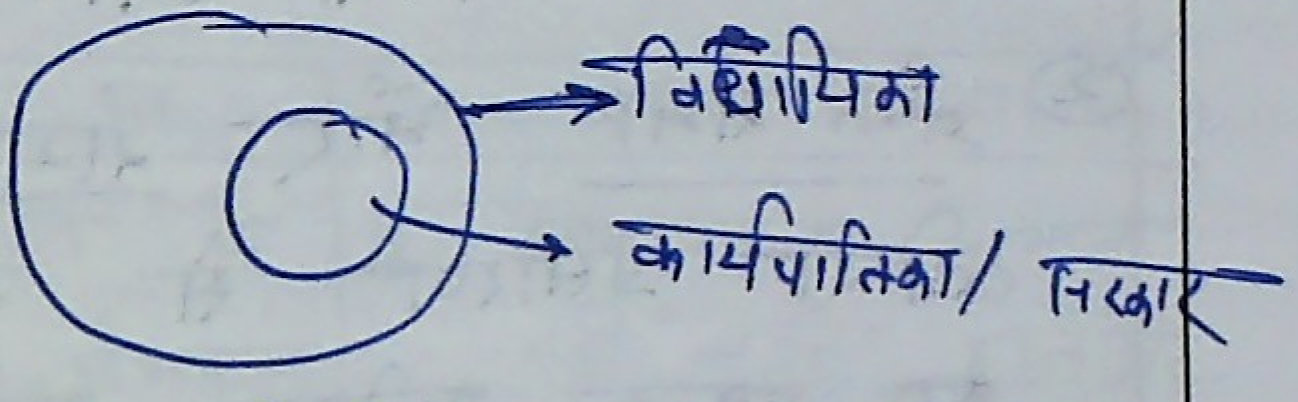

कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण

① अविश्वास प्रस्ताव (A-75)
↳ कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी

② निंदा प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव,
↳ आदि संसद की गरिमा को महत्व

③ प्रश्न काल, शून्य काल, आधे घण्टे की चर्चा
↳ सरकार की जवाबदेहिता बढाते है

④ संसदीय समितियाँ
↳ कानून निर्माण, मुद्दो सुलझाने में मदद

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

सीमाएं

① अविश्वास प्रस्ताव के चलते सांसद/ विधायकों की खरीद फरोख्त (हार्सट्रेडिंग) दल बदल की संभावना, बनी रहती है
उदाहरण. कर्नाटक और गोवा विधान सभा

② लोक सभा और राज्यसभा का सीधा प्रसारण से राजनेता दिखावे का प्रयत्न अधिक करते हैं। वास्तविक बहस कम

③ संसदीय समितियाँ → बढ़ता राजनीतिकरण
→ सदस्यों की अनुपस्थिति
→ विधेयकों को संसदीय समिति को न सौंपा जाना

समग्रत: संसदीय व्यवस्था को सुचारु ढंग से क्रियान्वित करने हेतु यह जरूरी है। कि कार्यपालिका की जवाबदेहिता अत्यधिक हो

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

5. राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बीच विभेदन कीजिये। सरकार की नीतियों को प्रभावित करने हेतु दबाव समूहों द्वारा कौन-से प्रमुख तरीके अपनाए जाते हैं? (150 शब्द) 10

Distinguish between political parties and the pressure groups. What are some of the prominent ways in which pressure groups try to influence the policies of the government? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

दबाव समूह की प्रक्रिया यूं तो राजनैतिक दलों जैसी प्रतीत होती है किन्तु इनमें भिन्नताएँ विद्यमान है

राजनैतिक दल	दबाव समूह
1. चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से संसद में प्रतिनिधित्व करते है।	1. साधारणतः चुनाव नही लड़ते, हालांकि राजनैतिक दलों को अहम समर्थन प्रदान कर सकते है
2. सत्ता पक्ष के विरोधी राजनैतिक दल ऐसे मांगे मनवाने हेतु दबाव समूहों से समर्थन ले सकते हैं	2. मूल कार्य सरकार से अपनी मांगे मनवाने हेतु दबाव बनाना
3. सामान्यतः संगठित स्वरूप से युक्त होते है।	3. सामान्यतः असंगठित स्वरूप
4. राजनैतिक दल जनता के वोट प्राप्त करने हेतु उनके नजदीकी बढ़ाते है	4. लाबिंग, भूख हड़ताल, सत्याग्रह जैसे अनेक तरीके अपनाते है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

तरीके

① आंदोलन – किसी मुद्दे पर आंदोलन द्वारा सरकार को झुकाना
उदाहरण हेतु इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के माध्यम से अन्ना हजारे आंदोलन – लोकपाल बिल

② भूख हड़ताल / सत्याग्रह / धरने
किसानों द्वारा अपनी मांग मनवाने हेतु ऐसे प्रयास
उदाहरण – भाकियू (भारतीय किसान यूनियन)

③ लॉबिंग
व्यावसायिक स्तर पर नीतियाँ प्रभावित करने हेतु
उदाहरण, FICCI, नीरा राडिया

④ हिंसक आंदोलन
आरक्षण संबंधी जाट आंदोलन

सारांशतः दबाव समूह भारतीय राजनैतिक व्यवस्था में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करते हैं।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

6. जहाँ एक ओर सरोगेसी (विनियमन) विधेयक 2019 भारत में सरोगेसी से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करता है, वहीं दूसरी ओर इसकी कमियों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। चर्चा कीजिये।
(150 शब्द) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

While the Surrogacy (Regulation) Bill 2019 does address various issues relating to surrogacy in India, its drawbacks can not be overlooked. Discuss. (150 words) 10

सेरोगेसी से तात्पर्य ऐसी सेवा से है। जिसमें किसी अन्य महिला द्वारा किसी युगल के भ्रूण निषेचन के माध्यम से अपने गर्भ में बच्चा पाला जाता है।

सेरोगेसी ~~बिल~~ ~~कि~~ 2019 ~~कि~~ द्वारा निम्न मुद्दे संबोधित किए गए हैं

1. परोपकारी सेरोगेसी
- अब सिर्फ जरूरत मंद लोगों को ही सेरोगेसी सेवा लेने हेतु अनुमति
- व्यावसायिक सेरोगेसी पर प्रतिबंध
- शादी के बाद 5 वर्ष तक बच्चा न होने पर ही अनुमति
- या दुर्लभ रोगों से पीड़ित महिला के संदर्भ में ~~अनु~~ अनुमति

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

2. सेरोगेट मदर के शोषण की समाप्ति

- पहले पूरा क्षेत्र अविनियमित था अब सेरोगेट मदर संबंधी पूरा डाटा रहेगा
- धन आधारित सेरोगेसी प्रतिबंधित
- बच्चे को लेना - दंपति का कानूनी दायित्व होगा

कमियां

- ① सेरोगेसी के माध्यम से भारत में बेहतर आर्थिक अवसर प्राप्त होते थे।
- ② सेरोगेट मदर प्राप्त करने में कठिनाई क्योंकि सेरोगेट मदर का निकट संबंधी होना आवश्यक है।
- ③ अभी भी अवैधानिक रूप से होने वाली सेरोगेसी रोकने का प्रयास नहीं दिखता।

निष्कर्षत: सेरोगेसी संबंधी सुविधाएँ मानवता के संदर्भ में होनी चाहिए नाकि शारीरिक सुख से बचने या धन के माध्यम से ऐसी सुविधाओं पर प्रतिबंध होना चाहिए

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

7. यद्यपि स्थानीय चुनाव लड़ने के लिये न्यूनतम शिक्षा की अनिवार्यता एक प्रगतिशील कदम है, किंतु इस कदम के साथ मौजूदा चुनौतियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। टिप्पणी कीजिये।

(150 शब्द) 10

While mandating minimum education criteria for contesting local elections is a progressive move, the associated challenges with this move can not be ignored in the current scenario. Comment. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा और राजस्थान (अब हटाया) जैसे राज्यों ने स्थानीय चुनाव में चुनाव लड़ने हेतु शिक्षा की अनिवार्यता निर्धारित की थी।

प्रगतिशील कदम

1. जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि का जागरूक, शिक्षित होना अति आवश्यक
2. विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में शिक्षित प्रतिनिधि अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है।
3. जन सहभागिता बढ़ाने, भ्रष्टाचार कम करने, सेवा सुपुर्दगी को बढ़ाने में, असमानता कम करने में शिक्षित प्रतिनिधि अहम योगदान दे सकता है।
4. ~~दक्षि~~ साक्षरता दर बढ़ाने में

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

एक इंसेंटिव के रूप में कार्य करेगा

चिंताएँ

1. शिक्षित और समझदार दो अलग अलग अवधारणा, संभव है कि एक असाक्षर व्यक्ति साक्षर व्यक्ति से अधिक समझदार हो

2. भारत की अभी भी ~~...~~ 25% जनसंख्या निरक्षर है।

3. अनुभव के बजाय शिक्षा पर अधिक बल। जबकि कभी-कभी अनुभव ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।

आगे की राह

1. ① शिक्षा संबंधी प्रावधान प्रगतिशील जरूर किन्तु किसी को चुनाव लड़ने से वंचित करना भारतीय लोकतंत्र के विरुद्ध है। बेहतर होगा कि ऐसे निरक्षर प्रतिनिधियों ~~हेतु का~~ तथा प्रत्याशियों हेतु साक्षरता की व्यवस्था की जाए। तभी इसे समावेशी ढंग से लागू किया जा सकेगा।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

8. कठोर दंड देने के आडंबर में हमें पोक्सो (POCSO) अधिनियम के क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं से ध्यान नहीं भटकाना चाहिये। POCSO (संशोधन) विधेयक 2019 के संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिये। (150 शब्द) 10

The rhetoric over severe punishments should not deflect our attention from the problems related to implementation of POCSO Act so far. Discuss in the context of POCSO (Amendment) Bill 2019. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

हाल के वर्षों में बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार संबंधी अपराध दुगने हो गए हैं जोकि बच्चों की सुभेद्यता को दर्शाता है।

जिसके चलते POCSO अधिनियम के प्रावधानों को कठोर बनाया गया है

1. 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे/बच्ची से यौन शोषण/बलात्कार की अधिकतम सजा को बढ़ाकर फांसी कर दिया।
2. बलात्कार (नाबालिग) के मामले में अधिकतम सजा - 20 वर्ष

आडम्बर कैसे

① कानून का अनुपालन न होना
② सजा मिलने में अत्यधिक देरी

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

→ वास्तविक मामलों से अत्यधिक कम रिपोर्टिंग

→ हाल के उन्नाव विधायक मामला, कठुआ मामले में प्रशासनिक तंत्र की अकर्मण्यता सर्वविदित है। जिसे सुधारने की आवश्यकता है।

सुधार कहाँ हो

→ ~~प्रशासनिक तंत्र / पुलिस तंत्र~~

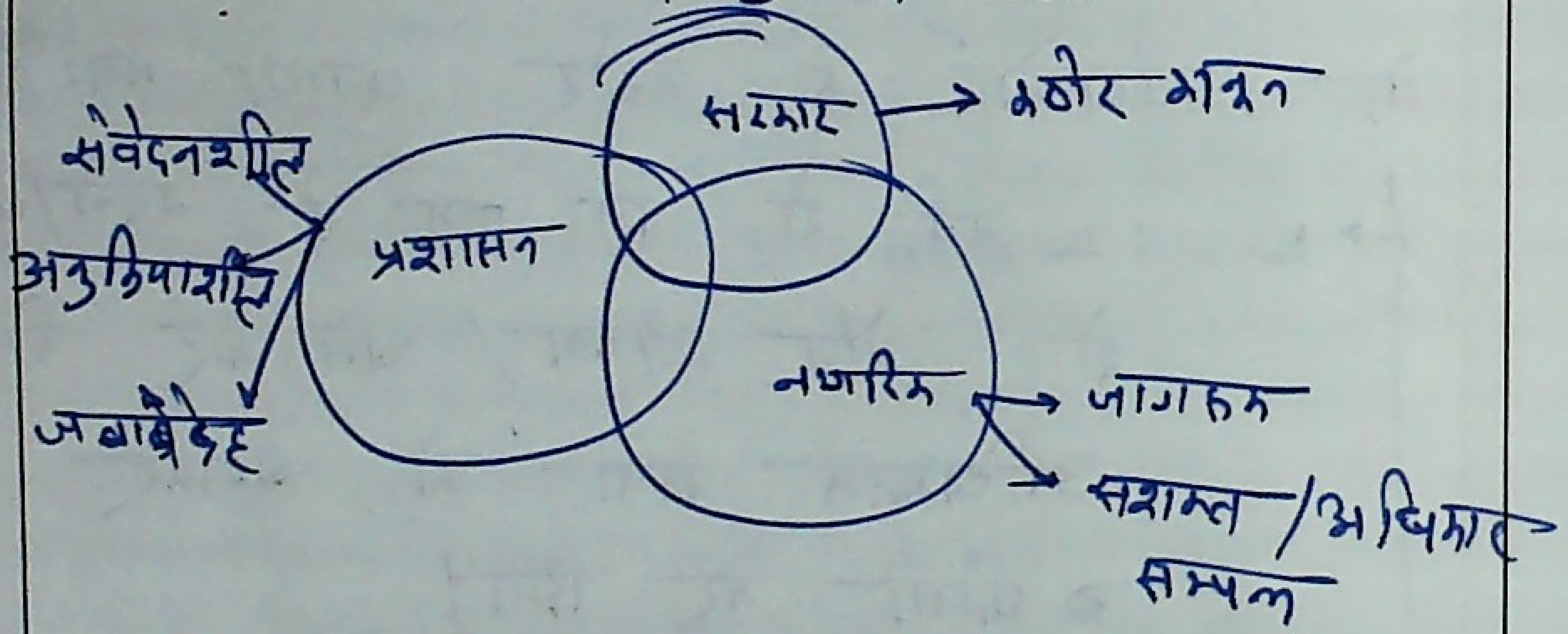

② फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से पीड़ित को त्वरित न्याय

सारांशतः POCSO अधिनियम में परिवर्तन सराहनीय है किन्तु इसके बेहतर परिणाम हेतु न्यायिक और पुलिस तंत्र की सुदृढ़ता पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है

Copyright – Drishti The Vision Foundation

9. हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन (ओ.आई.सी.) की बैठक में भारत की भागीदारी को 'ऐतिहासिक' क्यों कहा गया है? भारत के लिये इसका क्या भू-राजनीतिक महत्त्व है? (150 शब्द) 10

Why the recent participation of India in the Organization of Islamic Cooperation (OIC) meeting has been termed 'historic'? What is its geopolitical significance for India? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

हाल ही में पाकिस्तान के कठोर विरोध के बावजूद OIC में भारत की भागीदारी को हरी झंडी मिली।

ऐतिहासिक क्यों

① इससे पूर्व जब हमने प्रथम OIC बैठक में भाग लेने का प्रयास किया था तब भारत को पाकिस्तान विरोध के चलते शर्मिंदगी के साथ लौटना पड़ा था

② यह भारतीय कूटनीति की बड़ी असफलता थी

③ भारत सर्वाधिक मुस्लिमों की संख्या में दूसरे स्थान पर है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भू-राजनैतिक महत्व :

1. मुस्लिम बहुल देश जो सामान्यतः हर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देते थे। उन्होंने भारत का साथ दिया जोकि दिखाता है कि भारत का भू-राजनैतिक महत्व अत्यधिक है।

2. पाकिस्तान के विरोध को सभी देशों ने नकारा

3. OIC देशों में ऊर्जा संसाधन समृद्ध देश - अतः भारत की ऊर्जा सुरक्षा हेतु आवश्यक था।

4. हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती भारत की ताकत को निरूपित करता है

सारांशतः OIC देशों द्वारा भारत को प्रवेश देना भारत की विश्व व्यवस्था में बढ़ती धमक को प्रदर्शित करता है। भारत को आगे भी OIC में पूर्ण सदस्यता का प्रयत्न करने हेतु कूटनैतिक प्रयास करने चाहिए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

10. हाल ही में विदेश मंत्रालय ने एक समर्पित भारत-प्रशांत विभाग की स्थापना की है। इस संदर्भ में भारत के लिये भारत-प्रशांत क्षेत्र के भू-राजनीतिक महत्त्व का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

Recently the Ministry of External Affairs has setup a dedicated Indo-Pacific division. In this context examine the geo-political significance of the Indo-Pacific region for India. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

हाल ही में इंडो पैसिफिक का बढ़ता महत्व निम्न रूप में दिखता है।

1. भारत - प्रशांत विभाग की स्थापना
2. USA द्वारा एशिया पैसिफिक की जगह इंडो पैसिफिक शब्द
3. हवाई द्वीप कमाण्ड का नाम बदल इंडो पैसिफिक कमाण्ड

भारत के लिए भारत प्रशांत क्षेत्र का भू - राजनैतिक महत्व

1. चीन कारक
   - चीन को प्रतिसंतुलित करना
   - चीन की String of Pearls, OBOR के माध्यम से हिंद महासागर में बढ़ते कदमों को संतुलित करना
   - मालदीव, श्रीलंका (हंबनटोटा) इत्यादि के रूप में चीन की मजबूत स्थिति को प्रतिसंतुलित करना

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

2. **सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन**
- स्वतंत्रता बनाना
- अधिकांश तेल व वस्तु व्यापार का आवागमन हेतु ~~[illegible]~~ इंडो पैसिफिक महत्वपूर्ण

3. समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, पाइरेसी से इंडो पैसिफिक को मुक्त रखना

भारत के प्रयास
- प्रोजेक्ट मौसम
- FIPIC
- SAGAR Approach
- IORA, IONS, BIMSTEC, इत्यादि सहयोग
- सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे पर लॉजिस्टिक सुविधा प्राप्त
- सिसेल्स - असम्पशन द्वीप
- ओमान - दुक्म बंदरगाह

समग्रत: इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत का बढ़ता उभार भारत का मजबूत क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरना दर्शाता है। आने वाले वर्षों में यही कदम भारत को एक महाशक्ति के रूप में आगे ले जाने में सक्षम होंगे।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

11. भारत में हाल ही में कौन-से चुनाव सुधार लागू किये गए हैं? आपके अनुसार चुनाव सुधार संबंधी किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाना अभी शेष है? (250 शब्द) 15

What are some of the recent electoral reforms introduced in India? Which issues, according to you, still remain to be addressed as far as electoral reforms are concerned? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

लोकतांत्रिक देश में चुनाव का महत्व अतुलनीय होता है। चुनावों के माध्यम से ही जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है।

हाल के चुनाव सुधार

① फंडिंग संबंधी
- नकद के रूप में दी जाने वाली फंडिंग सीमा को 20,000 से घटाकर 2,000 किया
- इलेक्टोरल बांड के माध्यम से फंडिंग व्यवस्था में पारदर्शिता लाने व काला धन रोकने का प्रयास

② राजनैतिक अपराधीकरण रोकने संबंधी
- लिली थॉमस केस द्वारा RTI धारा 8(4) को अवैध
- अब सजा मिलते ही सदस्यता खत्म
- RPA - Act धारा 8(3): 2 साल से अधिक सजा पर 6 साल निलंबन
- 12 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

↳ सुप्रीम कोर्ट द्वारा ~~स्थानीय~~ अधीनस्थ न्यायपालिका को प्रतिनिधियों के मामले को 1 साल के भीतर निपटाने का निर्देश

चुनाव प्रक्रिया संबंधी सुधार

- EVM की विश्वसनीयता बढ़ाने हेतु VVPAT
- मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सुचारु क्रियान्वयन।

भावी सुधारों की रूपरेखा

① **राजनैतिक दल के स्तर पर**

- अपराधीकरण को दलों के स्तर पर रोकने पर बल। 17वीं लोक सभा में 43% सांसदों ~~अपराध~~ पर केस दर्ज हैं।
- आंतरिक लोकतंत्र की जरूरत
- RTI के अंतर्गत लाया जाए

② महिला को 33% आरक्षण संबंधी बिल को पास करने की जरूरत

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

चुनाव आयोग संबंधी सुधार

- अन्य 2 EC को संवैधानिक संरक्षण
- मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने हेतु कॉलेजियम व्यवस्था, तथा संवैधानिक संरक्षण हो
- चुनाव आयोग का सचिवालय अलग हो

फंडिंग के स्तर →
- पारदर्शिता बनाने की आवश्यकता
- कारपोरेट फंडिंग को बैन
- State फंडिंग को अपनाया जा सकता।

वोटिंग संबंधी
- टोटलाइजर मशीन अपनाने
- सभी EVM → VVPAT से लिंक

सारांशतः सुदृढ़ लोकतंत्र को बनाने हेतु इंद्रजीत गुप्त आयोग, 2nd ARC, विधि आयोग, संविधान समीक्षा आयोग इत्यादि ने भी इस तरीके के सुझाव दिए हैं जिन्हें अपनाकर हम चुनाव प्रणाली को अधिक सशक्त बना सकते हैं।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

12. भारत में मानव अधिकार आयोगों द्वारा सामना की जाने वाली संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं पर चर्चा करते हुए इन संस्थानों को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु उपाय सुझाइये। (250 शब्द) 15

While discussing structural and practical limitations faced by Human Rights Commissions in India, suggest measures to strengthen these institutions. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

मानव अधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के माध्यम से किया गया।

3 स्तर

- राष्ट्रीय स्तर → राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
- राज्य स्तर → राज्य मानव अधिकार आयोग
- जिला स्तर → जिला मानव अधिकार आयोग

संरचनात्मक कमियाँ

1. मानवाधिकार आयोग में अल्पसंख्यक आयोग से प्रतिनिधित्व का अभाव
2. आयोग के 2 अन्य सदस्य संबंधी योग्यताओं को निर्देशित नहीं किया गया
3. आयोग को 1 वर्ष से पुराने मामले पर कार्यवाही का अधिकार नहीं

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

4. अध्यक्ष के रूप में सुप्रीमकोर्ट मुख्य न्यायाधीश संबंधी प्रावधान v सीमित होते हैं अवसर

व्यावहारिक

1. स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति नहीं
2. अपने निर्णय को प्रवर्तित करने संबंधी शक्ति का अभाव
3. फंडिंग के स्तर पर अधिक फंड के माध्यम कुशल कार्यबल अधिक सुविधाओं की आवश्यकता

सुदृढ़ता हेतु उपाय

1. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायधीश H.L दत्तू ने मानवाधिकार आयोग को दंतहीन सर्प की उपाधि दी जोकि इसकी शक्तियों की सीमाओं को दर्शाता है।
2. स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही करने की शक्ति प्रदान की जाए

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

3. निर्णय को लागू करने संबंधी शक्ति दी जाए। निर्णय न पालन पर अवमानना संबंधी दण्ड देने का अधिकार हो

4. 1 वर्ष पुराने मामलों संबंधी प्रावधान [crossed out] में ना कार्यवाही करने संबंधी प्रावधान हटाया जाए

समग्रत: मानवाधिकार आयोग के सुदृढीकरण की आवश्यकता अत्यधिक है ताकि Art. 21 के तहत गरिमा मय जीवन के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके तथा प्रस्तावना के नीति, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक न्याय की परिकल्पना को पूर्ण किया जा सके

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

13. भारत के प्रधानमंत्री ने निरंतर 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रणाली का आह्वान किया है। इस संदर्भ में भारत जैसे देश में एक साथ चुनाव आयोजित कराने के लाभों, चिंताओं और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

The Prime Minister of India has repeatedly called for a system of 'One Nation, One Election'. In this context discuss the advantages, concerns and challenges in holding simultaneous elections in a country like India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रणाली से तात्पर्य लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने से है। ध्यातव्य है कि भारत में 1967 तक चुनाव साथ ही होते रहे। हाल ही प्रधानमंत्री जी द्वारा इस मुद्दे को पुनः उठाया है।

लाभ

① प्रशासनिक कार्यकुशलता : बार-बार आचार संहिता लगने से होने वाले नीतिगत कार्यों में व्यवधान कम होंगे। और गवर्नेंस डेफिसिट की समस्या खत्म होगी

② लागत : एक साथ चुनाव लागत को लगभग आधा कर सकता है

③ सामाजिक समरसता / सौहार्द
↳ वोट बैंक की राजनीति (जाति, धर्म) इत्यादि के चलते सामाजिक वर्गों में

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

तनाव बढता है।

4. भ्रष्टाचार / काले धन की समस्या को लगाम लगेगी ध्यातव्य है कि चुनाव प्रचार खर्च में काले धन का अत्यधिक प्रयोग होता है।

5. बार-बार चुनाव से नेता हमेशा चुनावी मूड में रहते है फलत: संसद की कार्यकुशलता घटती है

Ex: प्रधानमंत्री द्वारा राज्य विधानसभा चुनाव में प्रचार

चिंताएँ

1. क्षेत्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दों के सम्मिलन की समस्या

2. बार-बार चुनाव नेताओं की जवाबदेहिता में वृद्धि करते है

3. एक साथ चुनाव हेतु अत्यधिक सुरक्षा बल संबंधी आवश्यकताएँ

4. EVM संबंधी अवसंरचनात्मक आवश्यकताएँ।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

चुनौतियाँ

① संवैधानिक
- अविश्वास प्रस्ताव संबंधी चुनौतियाँ
- A-356 जनित राज्य सरकार विघटन संबंधी चुनौतियाँ

इन चुनौतियों से निपटने हेतु संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी।

② राज्यों के भीतर सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण → क्योंकि एक साथ चुनाव हेतु कुछ राज्यों के कार्यकाल कम - ज्यादा करने पड़ सकते हैं।

संसदीय समिति रिपोर्ट, 2nd ARC रिपोर्ट आदि में भी एक साथ चुनाव की आवश्यकता दर्ज की गई है। जिसे क्रमिक तौर पर लागू किया जा सकता है। रचनात्मक विश्वास प्रस्ताव जैसे नवाचार अहम हो सकते हैं इसके साथ ही अन्य चुनाव सुधार (अपराधीकरण, महिला कोटा - 15%) पर भी जोर देना होगा।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

14. आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य क्षेत्र की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

The launch of Ayushman Bharat scheme is a significant step towards universal health coverage in India. Critically analyse. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

अनुच्छेद 47 में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य है। पिछले वर्ष शुरू आयुष्मान भारत योजना सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (U.H.C) को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

प्रावधान

1. SECC-2011 के अनुसार पिछड़े 10 करोड़ परिवारों को तृतीयक व द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल में 5 लाख/वार्षिक स्वास्थ्य बीमा
2. 1.5 लाख हेल्थ & वेलनेस सेंटर खोलकर निवारक स्वास्थ्य पर प्रर्याप्त बल देना।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

U.H.C प्राप्त में आयुष्मान की भूमिका

1. प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में हेल्थ & वेलनेस सेंटर की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

2. स्वास्थ्य संबंधी खर्च गरीब व्यक्ति के आउट ऑफ पॉकेट खर्च को बढ़ाते है। जोकि हर साल 5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे ढकेल देता है। अत: गरीबी कम करने में अहम भूमिका

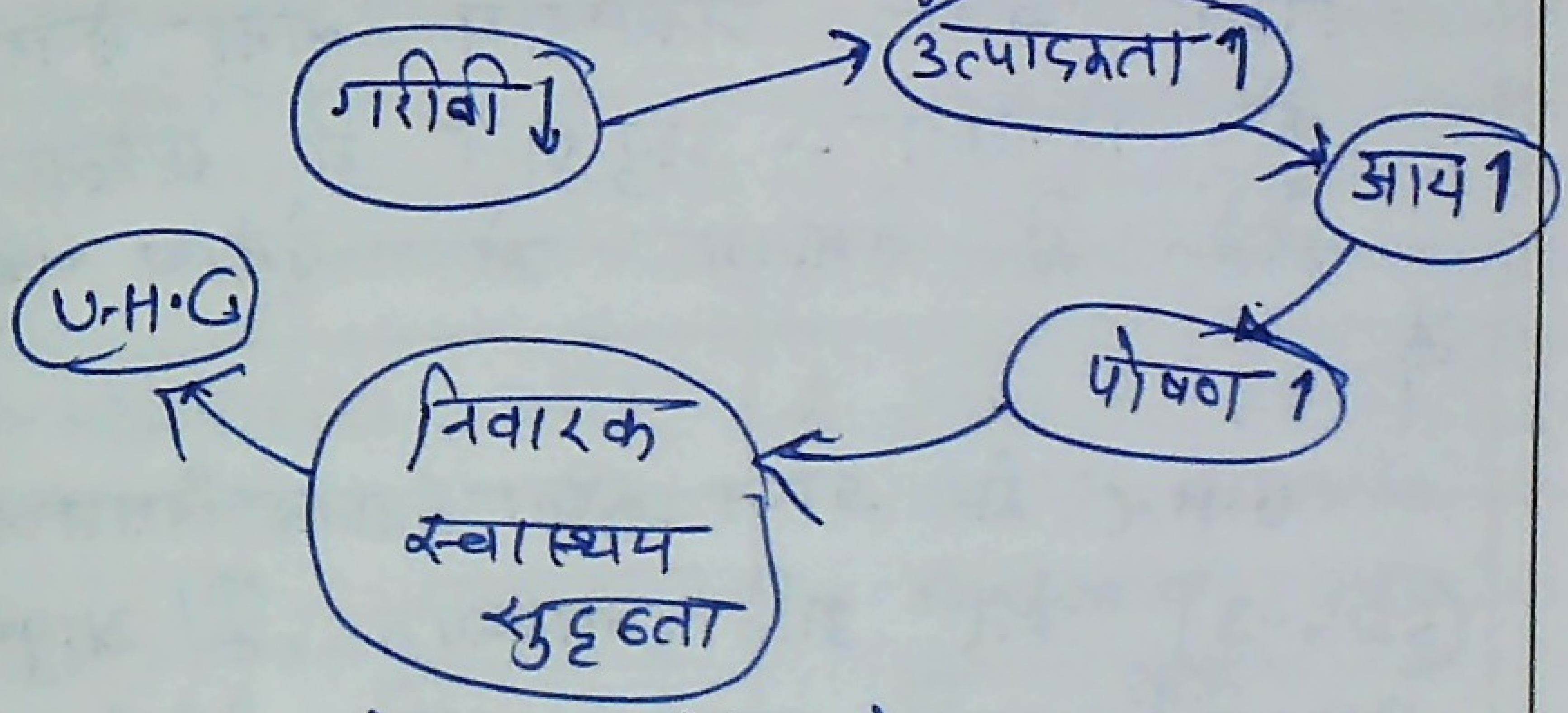

3. 10 करोड़ लोगों को शामिल करना ~~UHC~~ प्राप्त करने में बेहतर कदम है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इ
हाशिये में नहीं लि
चाहिये।
(Candidate must
write on this mar

चुनौतियाँ

1. सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर बीमा राशि नहीं
2. सिर्फ हास्पिटल में एडमिट होने पर बीमा का लाभ जबकि सर्वाधिक खर्च दवाईयों पर होता है। (60%)
3. अनैतिक चिकित्सा पद्धतियों रोकने को विशेष प्रयत्न नहीं। उदाहरण हेतु हास्पीटल बिल बढ़ाने हेतु अनावश्यक रिपोर्ट
4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय बीमा योजनाओं की विफलता - आयुष्मान की सफल होने की संभावना को संदिग्ध बनाती है।

U.H.C को प्राप्त करना सतत विकास लक्ष्य-(SDG-3) हेतु अति आवश्यक है। आयुष्मान मिशन के साथ साथ, सस्ती जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता बढ़ाकर, इम्यूनाइजेशन बढ़ाकर इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

15. सरकार की संसदीय प्रणाली के गुण और दोष क्या हैं? भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाने के क्या कारण थे? (250 शब्द) 15

What are the merits and demerits of the parliamentary system of government? What were the reasons for adopting parliamentary system in India? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

संसदीय प्रणाली से तात्पर्य है कि कार्यपालिका का चुनाव विधायिका से होगा। ब्रिटेन संसदीय प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है भारत में भी स्वतंत्रता बाद इसे ही अपनाया गया

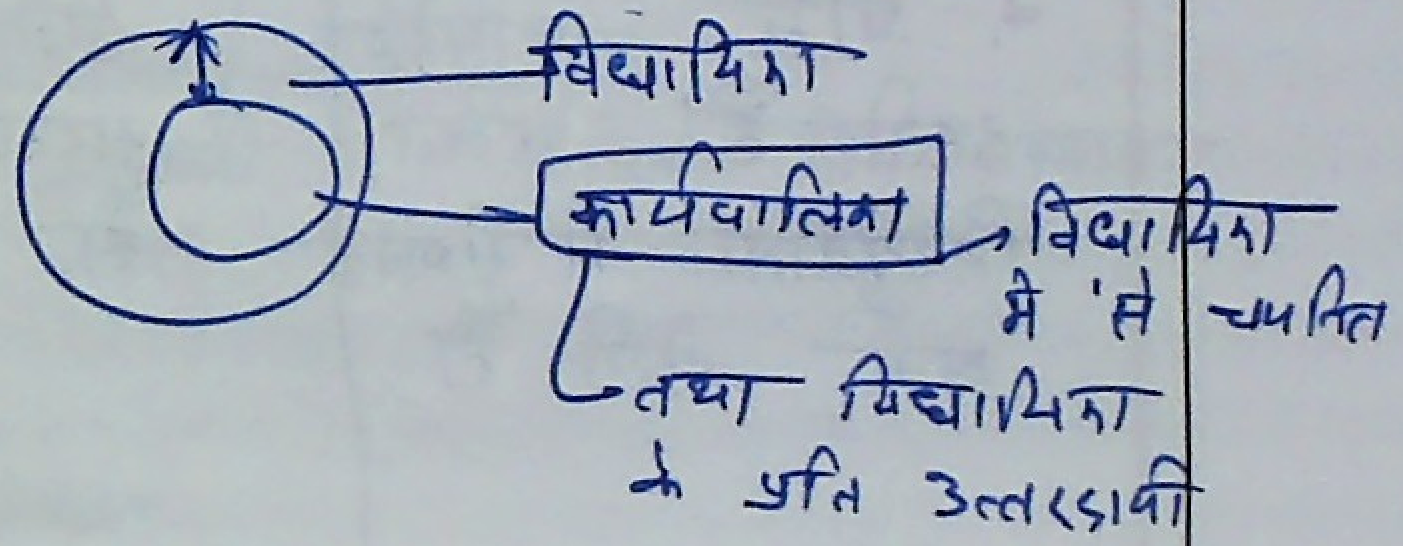

गुण	दोष
1. कार्यपालिका और विधायिका के बीच अनावश्यक गतिरोध की अनुपस्थिति होती है।	1. शक्ति के पृथक्करण का वास्तविक क्रियांवयन नहीं हो पाता
2. वैविध्य को महत्व मिल पाता है।	2. ~~[illegible]~~ मंत्री चयन में योग्यता से समझौता करना

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

3. अस्थिरता
- कार्यपालिका का विधायिका में विश्वास खत्म होते ही सरकार गिर जाती है।

3. जवाबदेहिता
- सरकार विधायिका के प्रति जवाबदेह रहती है। फलतः निरंकुशता की संभावना खत्म होती है

पड़ता है। क्योंकि संसद सदस्यों से ही मंत्री बनाने की बाध्यता होती है।

③ अस्थिरता
- कार्यपालिका का विधायिका में विश्वास खत्म होते ही सरकार गिर जाती है

उम्मीदवार को इ... हाशिये में नहीं ... चाहिये।
(Candidate must ... write on this ma...

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

अपनाने के कारण

1. सुपरिचितता : ब्रिटिश उपनिवेश के अंतर्गत चुनाव व्यवस्था संसदीय स्वरूप से ही युक्त थी

2: सरलता
→ जनता - निरक्षर थी (अधिकांश)
→ अतः संसदीय प्रणाली अपनाना अधिक उचित था

3. अत्यधिक विविधता
→ संसदीय प्रणाली में वैविध्य को सम्मान दिया जाता है।

~~निष्कर्ष~~

निष्कर्ष : अभी तक संसदीय शासन व्यवस्था सुचारु रूप से चलती आ रही है। जिसे और अधिक व्यवहार्य बनाने हेतु इसे अधिक से अधिक समावेशी और जनोन्मुख बनाना चाहिए

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

16. यद्यपि राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के बीच एक स्वस्थ संबंध सुशासन के लिये अत्यंत आवश्यक है, परंतु व्यवहार में दोनों के मध्य कई संघर्षपूर्ण क्षेत्र विद्यमान हैं। चर्चा कीजिये।

(250 शब्द) 15

Though a healthy relationship between the political executive and the permanent executive is critical for good governance but in practice there are multiple conflict areas in the relationship between the two. Discuss.

(250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सुशासन से तात्पर्य शासन की उत्कृष्ठता से है। जिसमें विश्व बैंक अनुसार निम्न तत्वों का समावेश होना चाहिए

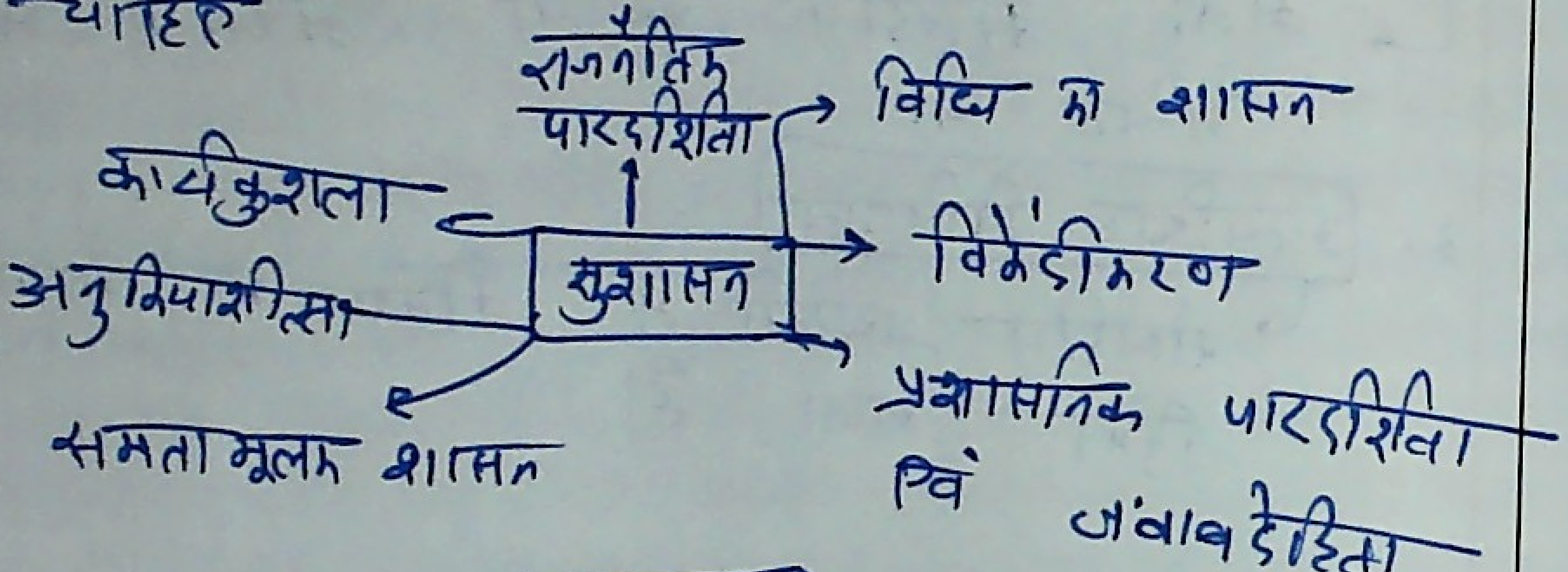

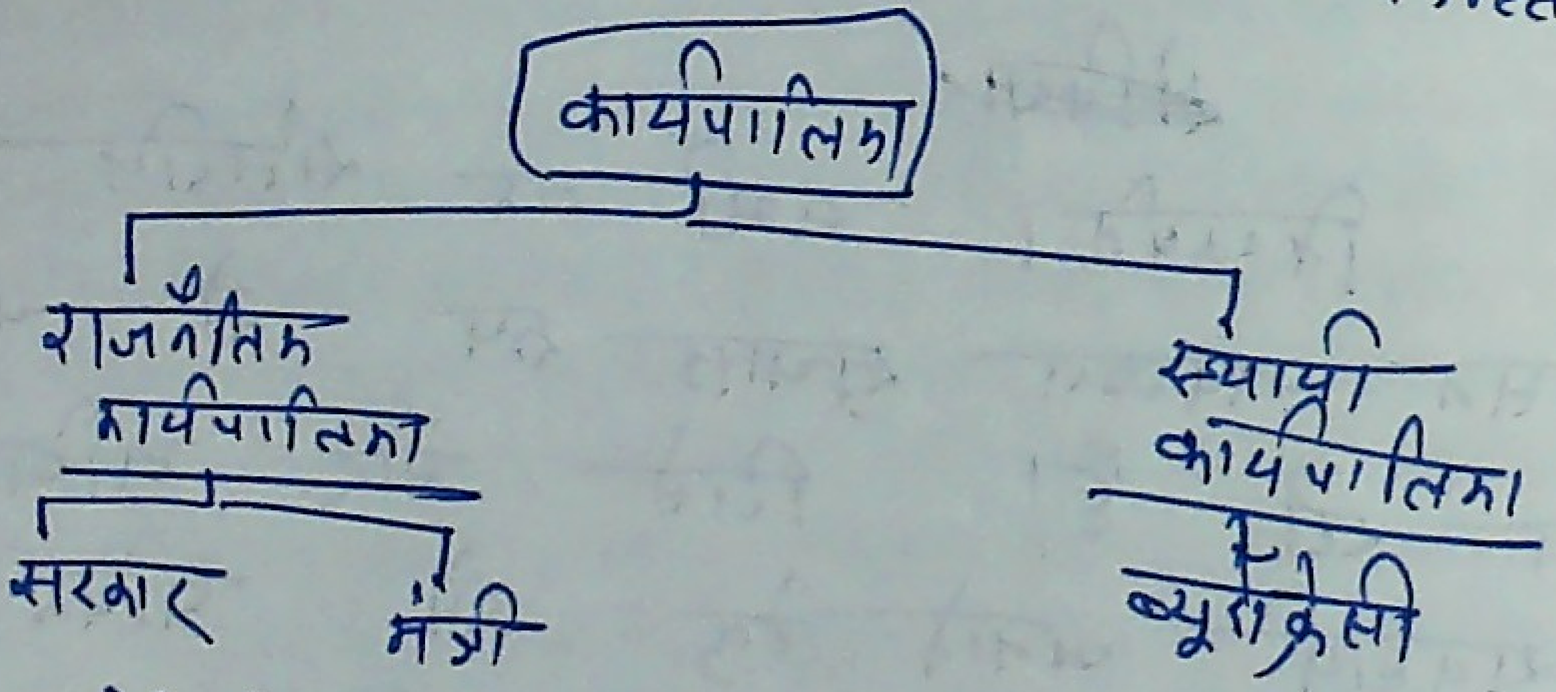

~~नीतियों~~

दोनों के मध्य स्वस्थ संबंध सुशासन को सुदृढीकरण कर सकते है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

1. बेहतर नीति निर्माण में राजनैतिक कार्यपालिका को प्रशासनिक अधिकारियों से सहयोग अपेक्षित होता है।

2. नीतियों के क्रियान्वयन में प्रशासन को प्रदत्त स्वायत्ता या राजनैतिक अहस्तक्षेप क्रियान्वयन की गुणवत्ता बढ़ायेगा फलतः सुशासन को बढ़ावा मिलेगा।

3. प्रशासन जनता और सरकार के बीच की कड़ी होती है। लालफीताशाही, भ्रष्टाचार, जैसे राजनैतिक हस्तक्षेप सुशासन की गुणवत्ता प्रभावित करते हैं।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

संघर्षपूर्ण क्षेत्र

1. ट्रांसफर → मनमानी पूर्ण ट्रांसफर
   → सरकार बदलते ही ट्रांसफर

2. भ्रष्टाचार → राजनीति प्रशासन गठजोड़ (क्लेप्टोक्रेसी)
   ↓
   अपने पंसद के प्रशासक से मेलजोल कर ईमानदार प्रशासन का ट्रांसफर करना

3. दोषारोपण → किसी नीतिगत विफलता या अन्य विफलता का दोषारोपण एक दूसरे पर

इन सभी समस्याओं को समाप्त करने हेतु सिविल सेवा बोर्ड का गठन किया जा सकता है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

17. वैकल्पिक विवाद समाधान (ए.डी.आर.) तंत्र के कई लाभ होने के बावजूद भारत में इसकी संभावनाओं का पूर्णतः उपयोग करना शेष है। विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

Despite having numerous advantages, the potential of Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanism remains underutilized in India. Analyze. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

वर्तमान में बढते न्यायिक विलंबन की स्थिति ने A.D.R तंत्र की व्यवहार्यता को बढावा दिया है।

न्यायिक स्थिति

- 3.5 करोड मामले लंबित
  - 60 हजार S.C.
  - 50 लाख H.C में
  - 3 लाख अधीन।
- 20% से अधिक रिक्तियाँ (अधीनस्थ न्यायालय में)

A.D.R

- मध्यस्थता
- आर्बिट्रेशन
- सुलह
- लोकअदालत
- न्याय पंचायत

मध्यस्थता → किसी मध्यस्थ के माध्यम से दोनों पक्ष समाधान तक पहुंचते हैं

आर्बिट्रेशन → पूर्व निर्धारित समझौते के आधार पर आपसी मामले का निपटान

सुलह — मध्यस्थता का ही एक प्रकार

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

लोक अदालत - सर्वाधिक सफल
 - प्रति वर्ष 50 लाख मामले निपटाये जा रहे।

न्याय पंचायत
 - ग्राम न्यायालय के माध्यम से

लाभ

1. कीमती समय की बर्बादी नहीं
त्वरित न्याय
2. अधिकांश मामलों में दोनों पक्ष लाभ की स्थिति में रहते हैं।
3. न्यायिक प्रणाली की खर्चीली, समय-साध्य प्रणाली का उपयुक्त विकल्प
4. वंचित वर्गों के अनुकूल
5. विदेशी निवेश आकर्षित करने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
6. मध्यस्थता की कुशल व्यवस्था
Ease of doing Business को बढाती है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

चुनौतियाँ

1. विशेषज्ञता का अभाव
2. निर्णय अंतिम नहीं होता अतः पुनः न्यायिक प्रणाली में जाने का विकल्प
3. मध्यस्थता संबंधी संस्थागत तंत्र एवं आयोगों की अनुपस्थिति
4. अंतर्राष्ट्रीय अनुकूल प्रणाली नहीं।

B.N श्री कृष्णा समिति ने A.DR प्रणाली की कुशलता संबंधी अनेक सुझाव दिए। ~~अतः~~ इन सुझावों को अपनाकर ना केवल ADR तंत्र की व्यवहार्यता को बनाया जा सकता है बल्कि इसे अधिक व्यापक बनाया जा सकता है। A.DR. की कुशलता आर्थिक व्यवहार्यता हेतु भी आवश्यकता है। हाल का आर्बिट्रेशन और मध्यस्थता संशोधन विधेयक में इन सभी चिंताओं को शामिल किया जा सकता है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

18. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, भारत के लिये अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष प्रावधानों को रद्द करने के संभावित निहितार्थों पर चर्चा कीजिये।

(250 शब्द) 15

While mentioning the key provisions of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act 2019, discuss the possible implications of scrapping of special provisions under Article 370 for India.

(250 words) 15

उम्मीदवार हाशिये में ... चाहिये। (Candidate ... write on th

पिछले महीने सरकार द्वारा संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में निम्न परिवर्तन किए।

1. A.370 को तत्काल प्रभाव से निरस्त
2. A.35(a) को निरस्त
   जोकि J&K के स्थायी निवासियों को परिभाषित करता था
3. जम्मू और कश्मीर → विधान सभा युक्त केंद्र शासित प्रदेश
4. लद्दाख → बिना विधान सभा का केंद्र शासित प्रदेश

A.370 अनुच्छेद को रद्द करने के अनुमानित निहितार्थ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

1 | सकारात्मक |

1. जम्मू व कश्मीर का एकीकरण शेष भारत से बढ़ेगी। और एकता और अखण्डता की अवधारणा मजबूत होगी।

2. केंद्रशासित प्रदेश बनने से विकास के अवसर सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रदान होंगे।

3. सुरक्षा → उग्रवादी घटनाएँ घटेंगी
→ अलगाववाद खत्म हो सकता है
→ सीमापार आतंकवाद से निपटने में सुदृढ़ता आएगी

4. आर्थिक → निवेश आकर्षित करने के अवसर
→ पर्यटन क्षेत्र का पुनरुद्धार हो सकता है।
→ औद्योगीकरण से रोजगार में वृद्धि की संभावना

हालांकि इस कदम के कुछ नकारात्मक परिणाम भी सामने आ सकते हैं

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को हाशिये में नहीं ... चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

नकारात्मक

→ न्यायालय से चुनौती मिल सकती है। J&K H.C तथा S.C द्वारा A-370 को अपने स्वरूप में कभी हद तक स्थायी माना है।

2. A-370(3) के अनुसार 370 को हटाने से पूर्व विधानसभा (संविधानसभा) की मंजूरी लेनी आवश्यक थी जो नहीं ली गयी।
   - अतः अविश्वास में वृद्धि हो सकती।
   - राजनैतिक स्तर पर क्षेत्रीय सहयोग प्राप्त करने में कठिनाई होगी।

3. J&K नागरिकों से A35(a) हटाकर विशेषाधिकार छीनने से वह प्रतिक्रियावादी रुख अपनाना सकते हैं फलतः सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी महत्वपूर्ण हो सकती है।

सरकार द्वारा लिया गया उपरोक्त कदम सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। बशर्ते हम जम्मू कश्मीर के लोगों को विश्वास में लें। और वहां आर्थिक, सामाजिक विकास पर ध्यान दें।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

19. क्या आप इस मत से सहमत हैं कि मालदीव में एक नई सरकार की स्थापना के साथ ही भारत-मालदीव के बीच संबंधों में मतभेद समाप्त हो गया है?

(250 शब्द) 15

With the inauguration of a new government in Maldives, do you agree that the rough patch in the relationship between India-Maldives is over?

(250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

पिछले वर्ष मालदीव में हुई चुनावों में सत्ता परिवर्तन हुई और अब्दुल्ला यामीन की सरकार अपदस्थ हुई। ध्यातव्य है कि अब्दुल्ला यामीन सरकार पर चीन समर्थक होने और भारत विरोधी होने के आरोप लगाए गए थे।

भारत विरोधी कार्य →
- GMR का एअरपोर्ट निर्माण का पट्टा रद्द किया
- वीजा संबंधी प्रावधान कठोर

चीन समर्थक →
- द्वीपों को चीन से लिया
- GMR Port का ठेका

नई सरकार - मोहम्मद - नासिर को भारत समर्थक माना जाता

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

ही जो जिन्होंने हाल ही अपने निर्णयों से यह स्पष्ट भी किया है।

→ तथा चीन की डेब्ट ट्रैप नीति की आलोचना भी की है

→ भारत को प्राथमिकता दी जा रही है

सारांशत: ~~भारत~~ मालदीव भारत के लिए अत्यधिक भू-राजनैतिक महत्व का है फलत: मालदीव की हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति के मद्देनजर अहम कदम उठाने की आवश्यकता।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

[illegible] सुरक्षा परिषद (यू.एन.एस.सी.) के सुधारों के प्रति भारत का क्या दृष्टिकोण है? इन सुधारों [illegible] में विलंब के क्या कारण हैं?

(250 शब्द) 15

[illegible] perspective on the United Nations Security Council (UNSC) reforms? What [illegible] delay in bringing out these reforms?

(250 words) 15

UNSC अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था का प्रतिनिधित्व करती है।

UNSC

स्थायी सदस्य — 5 सदस्य — अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस

अस्थायी सदस्य — 10 सदस्य

भारत का दृष्टिकोण : भारत UNSC में सुधारों का पक्षधर है और सुधार चाहता है।

① बदलती आर्थिक व्यवस्था
- विकासशील देशों का तीव्र उभार हुआ है और उनका प्रतिनिधित्व UNSC में नहीं है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार [illegible] हाशिये में [illegible] चाहिये। (Candidate [illegible] write on this [illegible]

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

(2) अफ्रीका से कोई प्रतिनिधित्व नहीं, जबकि UN के 70% कार्य अफ्रीका से संबंधित होते हैं।

(3). भारत - G-4 देशों के माध्यम से UNSC में सुधार की पेशकश करता है

G-4
- भारत
- जर्मनी
- जापान
- द. अफ्रीका

(4.) 1945 की व्यवस्था और 2019 की विश्व व्यवस्था में अत्यधिक अंतर आ चुका है

भारत
- अत्यधिक जनसंख्या वाला सबसे बड़ा लोकतंत्र
- ~~उभरती हुआ~~
- उभरती हुई महाशक्ति
- UN Peace Keeping force

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

में नवीनतम योगदान

विलंब के कारण

① राजनैतिक प्रतिबद्धता का अभाव
└ UN महासभा से 75% वोट से पास कराना होगा

② P-5 देश अपने अधिकारों में कटौती के पक्ष में नहीं

③ Veto Power संबंधी मुद्दे पर मतभेद

सारांशतः UNSC में सुधार बहुप्रतीक्षित है अगर संयुक्त राष्ट्र आधुनिक समय में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहता है तो इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation